भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2885
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

एफपीआई में स्वयंसहायता समूह

2885. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गांवों और शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को खाद्य प्रसंस्करण क्रियाकलापों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए कोई निधि स्वीकृत और जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संपूर्ण देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में ऐसे स्वयंसहायता समूहों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या हैं जिन्हें सहायता दी गई है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्र प्रायोजित पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के तहत, मंत्रालय एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को प्रारंभिक पूंजी के लिए 40,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान करता है। व्यक्तिगत एसएचजी सदस्य खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की एकल इकाई के रूप में परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। एसएचजी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की संबंधित घटक योजनाओं के तहत सहायता के लिए भी पात्र हैं।

(ग) से (ड.): पीएमएफएमई योजना का प्रारंभिक पूंजी घटक संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। 3,10,121 एसएचजी सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए 1032.31 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें से 31 अक्टूबर 2024 तक 2,47,984 ग्रामीण एसएचजी सदस्यों के लिए 810.89 करोड़ रुपये और 62,137 शहरी एसएचजी सदस्यों के लिए 221.42 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के अंतर्गत, 31 अक्टूबर, 2024 तक खाद्य प्रसंस्करण गतिविधि में लगे 692 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है ।

*****